B of the Schedule to the Act. Bidi-making is included in the Schedule to the Act and, therefore, the employment of children in Bidi making is prohibited under the Act. The respective State/UT Governments are the Appropriate Governments under the Act for detecting employment of child labour in Bidi sector. The State Governments through enforcement machinary, therefore, enforce the provisions of the Act with a view to prevent employment of children in all the prohibited occupations and processes including Bidi Sector. The Supreme Court of India in their judgement dated 10.12.96 has *inter-alia* given a number of directions regarding the manner in which children working in hazardous occupations including those in Bidi sector are to be withdrawn and rehabilitated. A number of steps have been taken for the implementation of the directions of the Court.

The Central Government monitors the overall enforcement of the Act on the basis of reports furnished by the State Government:;. Sector specific information regarding the enforcement of the Act, however, is not maintained.

खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे बाल-श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु नई योजना

254. **श्री इकबाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे बाल-श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई नई योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बाल-श्रमिकों का शोषण रोकने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए अब तक क्या-क्या प्रभावी उपाय किए हैं?

श्रम मंत्रालय के राजय मंत्री (श्री एम0 पी0 वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) इस परियोजनागत विधि के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत लगभग 2 मिलियन बच्चों के पुनर्वास के लिए अगस्त 1994 में एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित करना शामिल हैं। परियोजनाओं के अंतर्गत विशेष स्कूलों की स्थापना गैर-पारम्परिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणहार, वृत्तिका आदि प्रदान करने के लिए की जाती हैं। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले लगभग 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार विशेष स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिला दिया जा चुका हैं।

(घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची के भाग-अ और ब में वर्णित 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध न किये गये व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार की दशा विनियमित की जाती हैं। बालकों की रक्षा करने के लिए कारखाना अधिनियम, खन अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों आदि जैसे विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में उपबंध विहित हैं। सरकार का यह प्रयास रहा हैं। कि कामकाजी बालकों के हित की रक्षा करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवर्तित किया जाये।

Non-payment of compensation to workers of relocated industrial units

255. SHRI NARENDRA MOHAN:
Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the non-payment of compensation to the majority of workers of 169 polluting industrial units, being relocated out of the Delhi;

(b) if so, what steps have been taken so far to ensure that workers are paid compensation in accordance with decision of the Supreme Court; and

(c) whether any rehabilitation plan is being thought of, so that affected workers are gainfully employed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) According to information available from the Labour & Employment Department of the Government of NCT of Delhi the question of payment of legal dues to the workmen/employees due to shifting of industries out of Delhi as a result of the Supreme Court directive has received priority. They have indicated that teams were constituted and letters were issued to the management of the textile mills, where a large number of workmen are employed, to ensure compliance of the Orders of the Hon'ble Court.

(c) The Government of NCT of Delhi has taken steps to provide information/ guidance regarding location/availability and rates of industrial land available to facilitate rehabilitation of industries affected by the Supreme Court Orders.

Children below 14 years in Beedl Industry

256. SHRIMATI URMILA-BEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to answer to Unstarred question 4319 given in the Rajya Sabha on the 15th May, 1997 and state:

(a) the number of cases of employment of children below the age of 14 years detected and booked under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 during the last three years; and

(b) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य सिविल सेवाओं में आरक्षण

257. **श्री शिव चरण सिंह** : दया प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा जैसे प्रतियोगी परिक्षाओं के मामले में आरक्षण दिया जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा भी इसका अनुकरण किया जाता हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 आर0 बालासुब्रहमण्न) : (क) और (ख) जी, हां। संघ लोक सेवा आयोग इन परिक्षाओं में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता हैं।

(ग)और (घ) राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य सरकारों के अधीन सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती करते हैं। अत: उन्हें अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए यथा-निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करना अपेक्षित होता हैं।

Status of investigation into Security Scam

258. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present status of CBI investigations into the Security Scam of 1991-92; and

(b) whether it is a fact that the CBI has not taken any action against a former Planning Commission member involved in the scam; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) According to the information made available by the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs (Banking Division) and the CBI, so far, a total